भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 679

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2022 को दिया जाना है ।

29 आषाढ़, 1944 (शक)

उपभोक्ता सेवा केंद्र

679. श्री सुनील कुमार पिन्टू :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्रों को आधार कार्ड जारी करने की अनुमति देने का विचार है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आधार कार्ड प्राप्त करने में सुविधा हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि यूआईडीएआई ने अपनी शाखाओं के माध्यम से निवासियों को आधार नामांकन और अद्यतन सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों को रजिस्ट्रार के रूप में शामिल किया है । 30 जून 2022 तक, लगभग 11,700 बैंक शाखाएं निवासियों को आधार नामांकन/अद्यतन सेवा प्रदान कर रही हैं।

उपरोक्त के अलावा, सीएससी ई-गवर्नेंस के तहत कार्यरत लगभग 10,000 बैंकिंग संवाददाता आधार में जनसांख्यिकीय अद्यतन सेवा प्रदान कर रहे हैं।

******